even the poor do need some protein to survive. And in the circumstances, the prices of pulses have gone up. What can the poor do? And they go in search of this Kesari dal. So, when the Minister mentions about vested interests, now I would be very chary to consider the demand for survival of a human being as a vested interest. So, the problem lies in really increasing the aggregate production of pulses and this is something one should look into, why after 40 years of planned effort we have not been able to increase the production of pulses.

SHRI BALRAM JAKHAR: Mr. Chairman, Sir, this is a question we have to release and see what we have achieved in fifty years. It has been a saga of successes, the production going up from 50 million tonnes to 186.4 million tonnes. I know that there is deficiency as far as the pulses are concerned, but that also has not been stagnant. That has been going up. But what has been going up is our population You do not control it, That is the problem and with that, throughout the world....(Interruptions).... Just listen to me. Throughout the world there are deficiencies as far as the pulses are concerned. There is a shortage of pulses. We are trying to do away with it and we will do it because our scientists are competent. This is a rain-fed crop, most susceptible to diseases and whims of nature. That is why the farmers do not take up. We are trying to boost the farmers and give incentives to them so that they can produce more and we are on the job and we will do it.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 442.

Q. No. 442 (The questioner (Shri *Bhupinder Singh Mann*), *was absent. for answer, vide Col.....infra.*]

केन्द्रीय विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाया जाना

*443. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालयों में संस्कृत नवीं कक्षा तक ही पढाई जा रही है जबकि अन्य विद्यालयों में इसे दसवीं कक्षा तक पढाया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संस्कृत भाषा के शिक्षकों की कमी के कारण दसवीं कक्षा तक संस्कृत नही पढाई जा रही है, यदि हां, तो संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति में क्या बाधाएं हैं, और

(ग) सरकार केन्द्रीय विद्यालयों में दसवीं कक्षा तक संस्कृत पढाए जाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) संस्कृत को सभी केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा V से कक्षा IX तक तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से पढाया जाता है। केन्द्रीय विद्यालयो के छात्र समुदाय की संरचना को विचार में रखकर केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने यह निर्धारित किया है कि केन्द्रीय विद्यालय के प्रत्येक छात्र को बोर्ड में कक्षा X में दो भाषाओं के रूप में हिंदी और अंग्रेजी को अवश्य लेना चाहिए।

(ग) छात्र बोर्ड में कक्षा X में संस्कृत को भी एक अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में ले सकते हैं।

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : सभापति महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि,

"Students can also offer Sanskrit as an additional optional subject in Class X Board."

तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन सत्रों में कितने-कितने छात्रों ने दसवीं कक्षा में संस्कृत भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : सर, करीबन 100 विद्यार्थियों ने, 112 स्टूडेंट्स ने यह एडीशनल ओपशनल सब्जैक्ट के रूप में संस्कृत को लिया था।

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : नहीं, सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि पिछले तीन सत्रों में दसवीं कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने संस्कृत भाषा को अपनाया, परसेंटेज बताइये ?

MR. CHAIRMAN: You give the total number.

कुमारी शैलजा : सर, नैगलिजिबल परसेंटेज है । उसमें 818 स्कूल हैं और 112 स्टुडेंट्स ने आप्ट किया था और यह बहुत ही नैगलिजिबल है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : वन होगा ?

कुमारी शैलजा : वन भी नहीं होगा ।

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : सभापति महोदय, संस्कृत भाषा वह भाषा जोकि मानव जीवन के आदर्श और सच्चाई के मानदण्ड निर्धारित करती, मर्यादित और नैतिक जीवन की सीख देती है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करती है और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ करने में सहायक है । संस्कृत हमारे राष्ट्र की अनेक भाषाओं की जननी है, सस्कृत भाषा परिवार नियोजन का आधार नवयुवकों में रखती है, संस्कृत भाषा मानव जीवन को संयमित बना इंसान को निर्मल बनाती है । इन सब राष्ट्र हितकारी विशेष ताओं के रहने हुए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय संस्कृत भाषा को अनिवार्य दसवीं कक्षा तक बनाएंगे ?

कुमारी शैलजा : सर, वैसे भी जो स्टेपुलशन है और सी. बी. एस. ई. जो फोलो करता है , उसके हिसाब से हम स्कूल्स में छठवीं लेकर आठवीं तक संस्कृत भाषा को पढाते है, लेकिन केन्द्रीय विद्यालयों में हम इससे भी ज्यादा 5वीं कक्षा से 9वीं कक्षा तक पढा रहे हैं । फिर "ऐज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट" स्टुडेंट इसे एडशिनल ऑप्सनल सब्जैक्ट के रूप में भी ऑफर कर सकता है । तो उनके पास चॉइस है कि अगर वह 10वीं कक्षा में लेना चाहें तो ले सकते हैं । सर, इसके अलावा जो सी. बी. एस. ई. का पैटन है, उसके मुताबिक स्टूडेंट्स सब्जक्ट्स ऑफर करने हैं । उनके लिए दो लेंग्वेजेज होती हैं जिनमें एक तो अंग्रेजी या हिंदी हो और दूसरी हमारी माडर्न इंडियन लेंगवेजेज में से हो सकती हैं या फिर वह संस्कृत भी ले सकता है । सर, जो हमारी 29 लेंग्वेजेज हैं, उनमें से कोई भी लेंग्वेज स्टूडेंट ऑफर कर सकता है । यह हमारा फॉर्मूला है और इसके मुताबिक स्टुडेंट को संस्कृत का ऑप्शन भी है, अगर वह लेना चाहे ।

श्री शिव प्रसाद चनपुरिय : सभापति जी, मैं यही जानना चाहता हूं कि आप इसे अनिवाय बनाएंगे, इसकी उपयोगिता को देखते हुए, राष्ट्र हित में ?

कुमारी शैलजा : सर, 6वीं मे 8वीं कक्षा तक यह अनिवार्य है और उसके बाद भी अगर स्टूडेंट चाहे तो ले सकता है । उनके पास ऑप्शन है ।

श्री ईश दत्त यादव : : मान्यवर सभापति जी, श्री चनपुरिया, जी की जो जिज्ञासा हैं, उससे मैं सहमत हूं । मान्यवर, "चरक सुश्रुति" जैसा ग्रंथ जिस पर आयुर्वेद चिकित्सा चिकित्सा पदति चल रही है, यह सब संस्कृत भाषा में हैं । वेद संस्कृत में ई और हमारा पुराना विज्ञान भी संस्कृत में । संस्कृत इस देश की पुरातन भाषा है : इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मत्री जी से यह कहा चाहता हूं कि 5वीं से 9वीं कक्षा तक तो आप संस्कृत पढ़ाइए । वह आपने अनिवार्य किया हैं । और 9वीं व 10वीं का पाठ्यक्रम भी लगभग एकमा होता हैं फिर 10वीं के बाद ही स्टूडेंट को प्रमाण-पत्र मिलता है इसलिए अगर 9वी तक संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती है तो 10वीं तक संस्कृत की शिक्षा देने में आपको व्ययहारिक कठिनाई क्या हो रही है ? मेरे प्रश्न का "बी" पार्ट यह होगा कि क्या इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज तक संस्कृत पढ़ने के लिए सरकार गंभीरता से विचार करेगी ?

श्री माधवराव सिंधिया : सर, संस्कृत का महत्व हम भली-भांति समझते हैं । सस्कृत का स्थान भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और इसका बहुत गहरा प्रभाव कई दृष्टि से व्यक्ति, समाज और देश पर पड़ता है । इसलिए हम संस्कृत का

पूरा-पूरा महत्व समझते हैं और संस्कृत को प्रोत्साहित करने व इसके विस्तार की कई योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत हम संस्कृत का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। वह दूसरी योजनाएं हैं, लेकिन जहां तक मूल प्रश्न का सवाल है, जैसाकि मेरी साथी कुमारी शलजा जी ने कहा, संस्कृत 8वीं क्लास तक अनिवार्य है सी०बी०एस०ई० में और केन्द्रीय विद्यालय में हम इसे 9वीं क्लास तक पढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभी जो आपने सुझाव रखा है कि इस भाषा को 10वीं तक पढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपका सुझाव बहुत ही उचित है। और हमारा यह प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी दसवीं क्लास तक इसको लागू कराया जाए। हमारा पूरा पूरा प्रयास होगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद। क्या सब जगह ?

श्री माधवराव सिंधिया : हमारे के०वी० एस० केन्द्रीय विद्यालय में।

डा० संजय सिंह : माननीय महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी संस्कृत की आवश्यकता और संस्कृत के महत्व के बारे में बात कही, यह बड़ी खुशी की बात है। इसी से संबंधित में एक प्रश्न करना चाह रहा हूं माननीय मंत्री जी से, कि अगर वास्तविक रूप में भारत सरकार संस्कृत विषय के लिए, उसकी शिक्षा के लिए और उसके प्रचार-प्रसार की कोशिश कर रही है तो क्या कारण है कि संस्कृत विद्यापीठ बनारस से संबंधित जो विद्यालय है, संस्कृत के महाविद्यालय हैं, उसमें जो डिग्री बांटती है वह अन्य विषयों की डिग्री से फर्क रखती है, उसका महत्व कम होता है ? क्या कारण है कि उसमें जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनका वेतनमान बहुत कम है ? इसी वजह से, इसी कारण से बहुत सारे उन विद्यालय, उस विश्वविद्यालय से जो संबंधित हैं, मान लो अगर 100 विद्यार्थी एनरोल हैं तो 10 लड़के पढ़ने जाते हैं, कभी 5 लड़के पढ़ने जाते हैं। क्या माननीय मंत्री जी ऐसा प्रबंध करेंगे ताकि अन्य विषयों की डिग्री समतुल्य यथा डिग्री हो और अन्य विषयों के जो अध्यापक हैं उनके समतुल्य उनके वेतनमान हो जाए ?

श्री माधवराव सिंधिया : मान्यवर, यह प्रश्न जो है, यह केन्द्रीय विद्यालय से संबंधित है और जो उन्होंने जानकारी दी है, वह निश्चित रूप से सुझाव और जानकारी हमने नोट कर ली है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले दस, पन्द्रह वर्षों में भारत सरकार की तरफ से संस्कृत की रक्षा करने की जो एक पूरी कोशिश की गई थी, क्या उसको आप बदलेंगे ? आपने थ्री लेंगुवेज फार्मूला में संस्कृत को निकाल दिया और जहां आपने थ्री लेंगुवेज फार्मूला से संस्कृत को निकाला तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्केथिंग अटैक करते हुए भारत सरकार को यह कहा कि इतनी समझ नहीं कि संस्कृत का क्या महत्व है। सुप्रीम कोर्ट आपको सिखा रहा है कि संस्कृत को रखना चाहिए। आपने संस्कृत को डिलीट कर दिया और जब आपने संस्कृत को थ्री लेंगुवेज फार्मूला से डिलीट किया तो आपकी देखा-देखी यू०पी० गवर्नमेंट ने भी उसे डिलीट करने की कोशिश की। अगर यह सुप्रीम कोर्ट जजमेंट न देती तो आपने तो संस्कृत को निकाल ही दिया था और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी नहीं रखा था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और इधर बच्चों ने नौवीं में पढ़ना बंद कर दिया, दसवीं में पढ़ना बन्द कर दिया और इसीलिए 112 विद्यार्थी संस्कृत में आए क्योंकि लोगों ने सोचा कि अब थ्री लेंगुवेज फार्मूला में नहीं है, आगे ले ही नहीं सकते, संस्कृत पढ़ ही नहीं सकते तो इसको क्यों रखें। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा संस्कृत को प्रोत्साहन देंगे, आप नेहरु यूनिवर्सिटी चलाते हैं और इस नेहरु यूनिवर्सिटी में अरबी है, फारसी है, जर्मनी है, सब लेंगुवेज हैं, मगर संस्कृत नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Do not make statements. Please put your question.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसमें संस्कृत को भी लागू करेंगे ?

My question is whether the Ministry will introduce Sanskrit in the Jawaharlal Nehru University. The Minister says that they are going to do it.

वहां अरबी है, फारसी है, जर्मनी है, दुनियां की सब लेंगुवेज हैं और संस्कृत नहीं है।

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: The question is regarding Kendriya Vidyalayas and Sanskrit is taught in the kendriya Vidyalays have noted the centiments of the Members of Parliament and i will certainly try and take steps which would be in general consonance with the sentiments that emerge from this House from time to time. He have noted the suggestions. If they want details about other organisation, I am afraid, a separate notice will have to be given. But, fundamentally, we do understand the high importance of Sanskrit in our national system. We would do our best to find many ways and many avenues for adopting it and promoting it. A certain piece of information that the hon. Member has given is not factually correct.

Atrocities committed on SC/STs oustes from Rihand Super Thermal Power Plant

*444. SHR PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the atrocities committed on the oustees belonging to Scheduled Castes and weaker sections of the society, in Rihand Super Thermal Power Plant under NTPC;

(b) whether Government are aware that on 10th January, 1995 bulldozers and armed constables forced the villagers of Mitihini Village in Sonbhadra District of Uttar Pradesh for dispossession of their land;

(c) whether Government propose to investigation the matter; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESHRI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House. (a) and (b) Accordingly to information received from the Ministry of Power and the State Government of Uttar Pradesh, no atrocity was committed on the displaced persons belonging to Scheduled Castes and other weaker sections of the society in Rihand Super Thermal Power Plant of National Thermal Power Corporation. It has been further reported that no villager of Mitihini village in Sonbhadra District in Uttar Pradesh was ejected with the help of bulldozers and armed police force from his land. On 10th January, 1995, however, as there was apprehension of breech of peace, armed police force had to be deployed on the request of NTPC Authorities to commence construction on the land acquired in 1988 and 1989 and transferred to NTPC on 13-7-1989 and 10-1-1991

(c) No, Sir.

(d) Does not arise in view of what is stated at (a) and (b).

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Atrocities were committed on the backward people in a village in UP. Now the Government says that as per the report of the State Government, no atrocity was committed at any time. I had written three letters to hon. Shri S. B. Chavan, Shri Sitaram Kesri and Shri N.KP. Salve. They all promised me that an enquiry would be made. Now the Minister says even before the enquiry that no atrocity was committed. I do not know what the truth is, whether the atrocity was committed or not. But, Sir, the fact is that the NTPC needed 990 acres of land for the disposal of ash of the Rihand Super Thermal Power Project, for which an additional land of 650 acres was identified near Mitihini village. Mitihini village is a small village having 67 families and marginal farmers all of whom except one belong to the Scheduled Castes. These people are facing displacement for the second time. The first time was in 1960 as a consequence of the submergence caused by the Rihand Dam. The Rehabilitation Action Plan of the Mitihini village and the neighbouring Khairi village specifically states that no one will be displaced without being rehabilitated. As per this the allotment of agricultural lands should have been completed by December, 1994.